भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 464

06 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम

464. श्रीमती रचना बनर्जी:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के समन्वय से देश के चुनिंदा शहरों में शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (यूएफआरएमपी) शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि कोलकाता चयनित शहरों में से एक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की तिथि तक कोलकाता में संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक बरसाती जल (स्टॉर्म बाटर) प्रबंधन परियोजनाएं शुरू करने के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग) पंद्रहवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बाढ़ प्रबंधन के संबंध में समेकित समाधान तैयार करने के लिए मुंबई, चैन्नई और कोलकाता नामक तीन मेट्रो में से प्रत्येक के लिए राष्ट्रीय आपादा उपशमन कोष (एनडीएमएफ) से 500 करोड़ रुपए की धनराशि की सिफारिश की थी। आयोग ने शहरी बाढ़ के निवारण के लिए अहमदाबाद, बैंगलुरू, हैदराबाद और पुणे नामक चार शहरों में से प्रत्येक के लिए 250 करोड़ रुपए की धनराशि की सिफारिश भी की थी। एनडीएमएफ से आवंटन राज्यों के साथ लागत में साझेदारी पर आधारित है, जिसमें राज्य इन निधियों के 10 प्रतिशत का योगदान कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (यूएफआरएमपी) के अंतर्गत एनडीएमएफ से केंद्रीय हिस्से के रूप में 500 करोड़ रुपए के साथ कुल 650 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय से कोलकाता शहर के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है, ताकि संरचनागत और गैर-संरचनागत वर्षा-जल प्रबंधन परियोजनाएं शुरू की जा सकें। कोलकाता शहर को 150 करोड़ रुपए की पहली किस्त 13 नवंबर, 2024 को ही जारी की जा चुकी है।

एनडीएमए तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय शहरी बाढ़ की तात्कालिक एवं दीर्घकालिक चुनौतियों के समाधान के लिए राष्ट्रीय कार्यशालाओं के आयोजन के उद्देश्य से सहयोग करने के लिए सहमत हो गए हैं, जिनमें अधिक अनुकूल शहर तैयार करने के लिए जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों को शामिल किया जाएगा।

****